'ब्रह्मकुमार' जयपाल वकील सैक्स स्कैण्डल में गिरफ़्तार

करनाल (जे.के.-पी.के.) निर्भया काण्ड से प्रेरित होकर एक नया कानून महिला सुरक्षा के लिये बनाया गया जो पुलिस व कुछ वकीलों के लिये सोने की खान बन गया। इस कानून से अमीर लोग़ों के लिये एक नया डर उत्पन्न हो गया है। पुलिस विभाग को एक ब्रम्हास्त्र मिल गया है पुलिस विभाग के कुछ घटिया भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी, झूठा चोला पहनने वाले समाजसेवी, व वकील साजबाज होकर जिस्म फरौशी का धन्धा करने वाली पेशेवर व शुद्ध महिलाओं के साथ अमीर ग्राहक ढूंढने में लगाता है। अगर कोई अमीर या धनाढय व्यापारी इन महिलाओं के चंगुल में फंस जाता है तो पुलिस व वकीलों के इर्द-गिर्द व्यूह रचना शुरू कर देते है तथा बड़े गोपनीय ढंग से अपनी पहुंच बना लेते हैं और फंसे ग्राहक के खिलाफ़ सबूत हाने की बात कह कर समाज व कानूनी सज़ा का डर उत्पन्न का मोटी रकम ऐंठ रहें हैं। लेकिन ग्राहक का फ़िर भी पीछा नहीं छूटता एक जाता है फ़िर दूसरा आता है अगर कोई एक पक्ष सन्तुष्ट नहीं होता तो भाण्डा फुटने का डर। इसी प्रकार करनाल के कई व्यक्ति जिस्म फरौशी का धन्धा करने वाली पेशेवर महिलाओं के चक्कर में बदनाम हो चुके हैं। कुछ वकील भी इन महिलाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

करनाल में हाल ही में एक घटना घटित हुई है जिसमें समाज पुलिस विभाग व वकीलों में सनसनी फैल गई। काले कारनामें में लगे पुलिसकर्मी, महिलाओं के नाम पर कलंक, एक वेश्या व चर्चित वकीलों के एक गिरोह को नंगा करके रख दिया। अभी तक शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ़ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई वरना शामिल महिला व वकिलों के गिरोह के खिलाफ़ विशेष जांच दल ने अभियान चला रखा है। इस घटना की स्वयं पुलिस महानिदेशक निगरानी कर रहे हैं।

बताया जा रहा है कि करनाल के एक आभूषण व्यापारी जो सर्राफा बाजार करनाल में अपनी एक दुकान चलाता है के पास अम्बाला से एक युवती से पहले से ही सम्बन्ध था जिसने रमेश बंसल से सम्बन्ध स्थापित था। महिला पहले से प्रशिक्षित थी तथा वकीलों के ग्रुप के हाथ लग गई वकीलों ने उसे जासूसी करने के लिये फोन व वायस रिकार्डर दे रखे थे। व्यापारी युवती के रुप जाल में फंस गया तथा उसकी करतूत जयपाल वकील व हरीश आर्य व गौतम वकील गिरोह के पास ले गई। जिससे व्यापारी को ऐंठने की कवायद शुरू हो गई। वकीलों ने भी रमेश बंसल व्यापारी से सम्पर्क कर महिला के साथ सम्बन्ध होने के सबूत होने की बात कर समाज में प्रतिष्ठा खोने व कानून का डर दिखाकर जी भर कर लूटा जब युवती को लूट में हिस्सा कम मिलने पर पुलिस अधिकारियों से मिलकर व्यापारी के खिलाफ़ 376, 332, 353, 186, 120 बी एस सी एस टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया व 164 के तहत व्यान दर्ज करवाये दिया रमेश बंसल को जेल भेज दिया गया लेकिन इन वकीलों ने महिला को पैसा देने का वायदा कर ब्यान वापिस करवा दिया। वकीलों की आपसी फूट में महिला को पैसा नहीं दिया गया और नाराज महिला ने फिर से पुलिस से सम्पर्क कर कहा कि वकीलों ने जबरदस्ती ब्यान वापिस कराया है और मैं ब्यान वापिस नही लेना चाहती। पूरे प्रकरण में शहर पुलिस व वकील सन्देह के घेरे में आ रहे थे और कानून महिला को बचाने में लगा था। इस लिये पुलिस महानिदेशक वशिष्ठ ने विरेन्द्र शर्मा पुलिस निरीक्षक जिला कुरूक्षेत्र के नेतृत्व में एक विषेश जांच दल बना कर मामले की जांच में लगाया तो नित नये मामला सामने आने लगे। विशेष जांच दल के पुमुख विरेन्द्र शर्मा ने बताया कि कुछ महिलायें असरदार व्यक्तियों के साथ मिलकर इस प्रकार के कारनामें कर रही है और किसी न किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को निशाना बनाती है अय्यास किस्म के व्यक्ति की तलाश करती है। सुन्दर-सुन्दर लड़की को लाकर शिकार फंसाते हैं उसके बाद में लाखों के वारे न्यारे करते हैं, ये धन्धा लगातार चल रहा है।

जांच को आगे बढाते हुए विरेन्द्र शर्मा ने घटना में शामिल महिला से तमाम पहलूओं को उज़ागर करवा दिया तथा उसमें शामिल तीन वकीलों के खिलाफ़ वारन्ट गिरफ़्तारी ले लिया तथा एक वकील जयपाल को सैक्टर 13 से गिरफ़्तार कर लिया जबकि दो अभी भी भगौड़े बने हुये है हालाकि एक वकील हरीश आर्य प्रैस के माध्यम से अपने पास रिकार्ड की गई सी डी व बेगुनाह होने के सबूत जारी कर रहा है परन्तु पुलिस के सामने नही आ रहा।

करनाल बार ऐसोसियेशन ने भी मामले को गम्भीरता से लेते हुए नामजद वकीलों को बार से निलम्बित कर दिया। कुछ वकीलों से बात की गई कि अदालत का फैसला होने से पहले ही उन्हें क्यों निलम्बित किया तो उन्होंने बताया कि पहले भी इनके काले कारनामें चर्चित रहे हैं हमारे पास कोई सबूत न होने के कारण चुप रहे। इस बीच सुत्रों से पता चला कि जयपाल के बैंक खाते में लगभग 4.25 करोड़ का लेन-देन दर्ज है।

हरीश आर्य ने फाईट फ़ार जस्टिस कल्ब के नाम से एक एन.जी.ओ. बना रखी है तथा ऐसे मामलों को प्रशासन के सामने रखता है जिसके पीछे की सच्चाई क्या है ये इस प्रकरण से सामने आ गई।

जांच अधिकारी विरेन्द्र शर्मा के अनुसार करनाल के आसपास ऐसे गिरोह सक्रिय है जो आवारा किस्म की लड़कियों को मोटे पैसे का लालच देकर अमीर आसामियां फसा लेते हैं और मोटी रकम का लेन-देन करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस विभाग भी इसमें सीधे तौर पर शामिल है।

सर्राफ़ा व्यापारी को ब्लैकमेल करने वाले हरीश आर्य एक एनजीओ फाईट फॉर जस्टिस कल्ब ऑफ इण्डिया व वकालत की आड़ में ब्लैकमेल का घिनौना खेल खेल रहा है। मुख्यता रामनगर क्षेत्र के ऐसे झगड़ों को लेकर ये प्रशासन के खिलाफ़ आवाज उठाता रहा है प्राय: प्रेस नोट व प्रैस कांफ्रेस के द्वारा स्थानीय समाचारपत्रों में अपनी फोटो छपवाता है ताकि प्रशासन पर अपना प्रभाव बना सके।

वकील जयपाल के कई चेहरे है ये ब्रम्हकुमारी आश्रम, करनाल से जुड़ा हुआ है कभी अपने आप को भगवान कृष्ण का अवतार बताता है कभी ब्रम्हकुमारी आश्रम में सेवादार बनता है तथा इसके मित्र बताते हैं कि अयाशी का शौकीन है।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में एक घटना घटी कि करनाल के नगर निगम का बिल्डिंग इंस्पेक्टर हंसराज जो ब्रम्हकुमार बना हुआ है प्रतिदिन सुबह ६ बजे सदर बाजार के ब्रम्हकुमारी आश्रम आता-जाता रहता है वह भी एक रेप केस में करीब एक महीना से जेल में है जिसकी अभी तक जमानत नही हुई।

ब्रम्हकुमारी आश्रम, करनाल पर भी सवाल उठे हैं कि धर्म के नाम पर लोग़ों को गुमराह करके अनैतिक कार्य हो रहे हैं। लोग ब्रम्हकुमार जयपाल के गिरफ़्तार होने पर हैरान हो गये कि क्या ब्रम्हाकुमारी आश्रम धर्म के नाम पर ऐसे लोग पैदा करती है जो समाज को खराब करते हैं।

मॉऊट आबू से आई एक ब्रम्हाकुमारी ने सेक्टर 16 के बुजुर्ग के साथ सम्बन्ध स्थापित किये और बाद में उसको पुलिस केस करने की धमकी देकर 20 हजार रुपये ऐंठ लिये और चलती बनी। करनाल के एक सेवा निवृत्त सैशन जज के पास एक युवती नौकरानी बन कर आई व धीरे-धीरे सम्बंध स्थापित कर कानूनी कार्रवाई करने व इज्जत मिट्टी में मिलाने का भय दिखा कर पत्नि का दर्जा हासिल कर लिया इसी गम में कुछ माह बाद सैशन जज की मृत्यु हो गई और वह युवती अशोका कालोनी के आलीशान बंगला कब्जा कर पूरी सम्पत्ति की मालिक बन गई।

इसी तरह करनाल के एक ज़िला महान्यायवादी व उसका एक दोस्त युवती के चक्कर में फंस गये युवती का सम्बन्ध दलाल व वकीलों से था। मामला पुलिस तक भी पहुंचा लेकिन कुछ नामचीन आदमीयों ने बीच मतें पड़कर मामला 6 लाख रुपये देकर निपटा दिया।

सैक्टर 9 के रहने वाले एक व्यापारी को ८ लाख की चपत इसी चक्कर में लगी। स्थानीय ऋषी नगर करनाल का मामला भी काफ़ी चर्चित रहा सेक्टर 16 व इण्डस्ट्रीयल सेक्टर ३ के मामले जग जाहिर है लेकिन प्रशासन इन्हें संरक्षण दे रहा है।

कुल मिलाकर इज्जतदारों को अपने हुस्न के रूप जाल में फ़सा कर इज्जतदारों की आबरू का सौदा बदनाम गिरोह व पुलिस मिलकर कर रही है। कभी बचाने कभी फंसाने के नाम पर नित रोज खेल खेला जा रहा है कुछ ही मामले प्रकाश में आते हैं बाकि लूट की भेंट चढ़ जाते हैं।

सेटर 62 आशियाना-वासियों की दुर्दशा

बल्लबगढ (म.मो.) खेड़ीपुल से सेक्टर 29 व 17 की तरफ़ बाइपास के किनारे बसी किसान-मज़दूर कॉलोनी वालों को उजाड़ने के बदले सरकार ने सेक्टर 62 में एक आशियाना योजना बनाई। गुड़गांव नहर रूपी गंदे नाले व सड़क के दरम्यान बसी इस गंदी बस्ती में दिहाड़ीदार मज़दूर, रिक्शा चालक व इसी तरह की अन्य मज़दूरी करने वाले लोग बसे थे। करीब 30-40 साल पहले, सेक्टर 16 ए स्थित लक्षमण बाग की झुग्गियों को उजाड़ कर उन्हें यहां बसाया गया था। उस समय यह बाइपास न के बराबर था। सुनसान पड़ा रहता था।

आज जब बाइपास का महत्व बढा, इसे चौड़ा करने की जरूरत पड़ी तो झुग्गियां अखरने लगीं। कोर्ट के आदेश पर सरकार ने आशियाना में 36 वर्ग गज़ के फ्लैट बनाकर करीब 1100 परिवारों को यहां बसा दिया। खुली हवा में सांस लेने तथा अपने-अपने रोज़गारों के पास बसे इन लोग़ों को चारमंजिला दड़बेनुमा इन फ्लैटों में घुटन महसूस हो रही है। आसपास कोई काम न मिलने के चलते काम के लिये कई-कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बस सेवा न होने के चलते आटो आदि के द्वारा आवागमन बहुत ही मंहगा एवं कष्टदायक पड़ता है।

इतना ही नहीं इन फ्लैटों की मासिक किश्त भी सरकार ने 2700 रुपया रखी है। प्रतिदिन 150 से 300 रुपया की मज़दूरी कमाने वाले ये लोग किसी भी हाल में किश्त देने की स्थिति में नहीं हो सकते। ऐसे में भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी इन ग़रीबों को ब्लैकमेल करेंगे तथा कुछ दबंगों से मिलीभगत करके इन्हें फ्लैटों से बेदखल करने का प्रयास भी कर सकते हैं। इन हालात में फ्लैटवासियों को संगठित होकर भ्रष्ट एवं दबंगों की ब्लैकमेलिंग से लड़ते हुए फ्लैटों पर अपने कब्ज़े कायम रखने होंगे।

हैरानगी की बात तो यह है कि इसी आशियाना के बगल में बसे गांव साहूपुरा में बी पी एल श्रेणी के लोग़ों को सरकार 100-100 गज़ के प्लाट न केवल मुफ़्त दे रही है बल्कि घर बनाने के लिये पैसा भी दे रही है। क्या इन बी पी एल और उन बी पी एल में कोई अन्तर है? बी पी एल-बी पी एल के बीच यह भेदभाव कैसा?

दरअसल यहां एक और ड्रामा भी तो है; बी पी एल यानी ग़रीबी रेखा से नीचे तो केवल उसे माना जाता है जिसे सरकार का भ्रष्ट अधिकारी रिश्वत लेकर बी पी एल घोषित करे। इसका ग़रीब होने से कोई विशेष ताल्लुक नहीं है। झुग्गियों से आशियाना में लाकर बसाये गये लोग़ों को भी यदि चोरों की यह सरकार बी पी एल नहीं मानती तो फिर किसको बी पी एल मानेगी?

आशियाना में बसे अधिकांश लोग़ों के पास बी पी एल के बजाय साधारण राशन कार्ड हैं। जिन्होंने भ्रष्ट कर्मचारियों को रिश्वत देकर बी पी एल राशनकार्ड बनवाये थे वे अब पछता रहे हैं क्योंकि गेहूं चावल चीनी न तो नियमित रूप से इन कार्डों पर मिलता है न साधारण पर। फ्लैट नम्बर 908/23 में रहने वाले 64 वर्षीय महिपाल ने इस संवाददाता को बताया कि चंडीगढ से उसका बी पी एल नम्बर तो आ गया है पर अभी तक उसे बी पी एल कार्ड नहीं मिला। राशन कार्ड पर 2-3 माह बाद कभी चीनी तो कभी गेहूं मिल जाता है। बुढापा पेंशन भी उसे नहीं मिलती।

फ्लैट नम्बर 954/23 में रहने वाली मुन्नी के पास बी पी एल कार्ड तो है पर डिपो वाला उस पर उसे देता कुछ नहीं। जाने पर कह देता है कि अभी सप्लाई नहीं आई है, अगले हफ्ते पता करना। घुटनों के दर्द से परेशान मुन्नी का गैस कनेक्शन भी सेक्टर 28 का है, जहां वह पहले रहती थी। कनेक्शन न तो नजदीक में कहीं ट्रांसफ़र होता है और दूर से लाना बहुत कठिन है। सेक्टर 28-29 की कोठियों में जो घरेलू काम उसके पास था, वह भी छूट गया ऊपर से 2700 रुपया की किश्त मांगती हैं सरकार।

फ्लैट नम्बर 923/23 में रहने वाले सतपाल का भी यही रोना है। बी पी एल कार्ड का नम्बर तो चंडीगढ से आ गया है पर कार्ड नहीं मिला। फ्लैट नं. 947/24 में रहने वाले नवाब खां ने बताया कि जब कोई बस नहीं चला तो बी पी एल कार्ड बनवाने के लिये उसे अपने डिपो वाले को (ओल्ड फ़रीदाबाद) 400 रुपये नकद देने पड़े थे। उसने बताया था कि उसकी बड़े बाबू से सैटिंग है और वह उसका बी पी एल कार्ड बनवा देगा। पैसा भी गया और कार्ड भी नहीं मिला। अनीता ने जैसे-तैसे बी पी एल कार्ड तो बनवा लिया लेकिन मिलता उसे भी कुछ नहीं है। उसका पति राजू बी पी टी पी कम्पनी में मात्र 6000 मासिक की नौकरी करता है। इस मंहगाई में 5 लोग़ों के परिवार का गुजारा होना मुश्किल हो रहा है।

आशियाना में रहने वाले इन सभी निवासियों की यही कहानी है। न केवल आशियाना वासियों की बल्कि इस आयवर्ग के सभी लोग़ों की यही कहानी है। इनके लिये मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह की विज्ञापनबाज़ी व प्रधानमंत्री मोदी की नारेबाज़ी किसी छलावा मात्र से कम नहीं है।

राजमार्ग पर केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल की बाज़ीगरी

फ़रीदाबाद (म.मो.) दसियों बरस पहले यह निर्णय हो चुका था कि दिल्ली से आगरा तक राष्ट्रीय राजमार्ग को 6 लेन का किया जायेगा। करीब 5 वर्ष पूर्व इस काम को करने का ठेका देश के सबसे बड़े चोर तथा (भाजपा व कांग्रेस) दोनों सरकारों के चहेते अनिल अम्बानी की कम्पनी रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है।

सुधी पाठक भूले नहीं होंगे कि करीब 4 वर्ष पूर्व जब शहर में मैट्रो रेल का काम शुरू होने लगा था तो इस चोर कम्पनी ने काम में रुकावट डालकर 100 करोड़ रुपये ऐंठने का प्रयास किया था। अम्बानी के इशारों पर नाचते हुए एन एच आई ए (नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ़ इन्डिया)ने मैट्रो का काम रोकने के लिए मौके पर हाथापाई तक करने के लिये अपना स्टाफ़ कई बार भेजा था। अन्त में हरियाणा सरकार के इशारे पर थाना सेंट्रल पुलिस ने जब आंखे तरेरी तब जाकर कहीं एन एच ए आइ वाले अपनी औकात में आये।

उक्त गुंडागर्दी के पीछे एन एच ए आइ का तर्क यह था कि मैट्रों द्वारा काम शुरू करने से उनके ठेकेदार कम्पनी को सड़क चौड़ी करने के काम में काफ़ी दिक्कतें एवं परेशानी होगी, जिसके एवज में उसे बतौर मुआवज़ा 100 करोड़ रुपये दिलवाया जाय, जिसे मैट्रो एवं सरकार ने ठुकरा दिया तो एन एच ए आइ हाथापाई पर उतर आई थी। यह मुआवजा जाना अनिल अम्बानी के जेब में था।

अब देखने वाली बात यह है कि मैट्रो का काम लगभग पूरा हो चला है और सड़क का काम अभी ढंग से शुरू भी नहीं हुआ है। विदित है कि मैट्रो सड़क के केवल एक ही साइड में है। यदि रिलायंस कम्पनी की नीयत साफ़ थी और वह काम करना चाहती थी तो दूसरी तरफ़ काम शुरू कर सकती थी। लेकिन किया कुछ नहीं, क्योंकि व सरकारों की लाडली इस कम्पनी को कमा कर खाने की आदत तो है नहीं, हमेशा हरामखोरी पर नीयत रहती है।

पिछले करीब दो सप्ताह से केन्द्रीय मन्त्री कृष्णपाल इस राजमार्ग पर बाज़ीगरी करते घूम रहे हैं। इसके निर्माण कार्य में तेज़ी के साथ-साथ डिज़ाइन में भी संशोधन आदि की बातें कर रहे हैं। इस दौरान यह भी सुनने में आ रहा है कि इन संशोधनों से निर्माण लागत 3000 करोड़ से बढ कर 5000 करोड़ तक पहुंच जायेगी।

सवाल यह समझने वाला है कि इस लागत अथवा खर्च में से कृष्णपाल की केन्द्र सरकार कितना खर्च कर रही है? एक चवन्नी भी नहीं। सूखी चौधर दिखा रहे हैं। सारे खर्च का तीन-चार गुणा सीधे जनता से वसूल कर ही खर्च किया जाने वाला है। जिस रिलायंस कम्पनी को निर्माण कार्य का ठेका दिया गया है, उसे टोल टैक्स के माध्यम से जनता को लूटने की खुली छूट पहली सरकार ने भी दे रखी थी और इस सरकार ने भी। फ़रीदाबाद से आगरा तक दो जगह टोल के माध्यम से जनता को लूटा जा रहा है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार यह लूट कमाई एक से डेढ करोड़ प्रति दिन की है तथा पिछले कई बरसों से चल रही और यदि ऐसी ही सरकारें रही तो उम्रभर चलती रहेगी।

जहां तक सवाल है निर्माण कार्य की गति का तो उसे टोल वसूली के हिसाब से चलाया जा रहा है। जितना टोल वसूल होता है उसका बमुश्किल एक चौथाई भाग ही इस कार्य पर खर्च किया जाता है। समझना कोई मुश्किल नहीं है कि यह सारी लूट अम्बानी अकेला तो हजम नहीं कर रहा। इसमें एक बड़ा हिस्सा उन सब लोग़ों का भी होता है जो उसे यह लूट वसूलने में मदद कर रहे हैं। मोदी के चुनाव अभियान पर जो हज़ारों करोड़ रुपया खर्च हुआ था वह इसी तरह की लूट वसूली से ही प्राप्त हुआ था।

दो से चार और अब चार से छ: लेन होने जा रहे इस राजमार्ग पर न तो पैदल चलने वालों के लिये कोई व्यवस्था की गयी है और न ही हज़ारों की संख्या में चलने वाली साइकिलों के लिये। पैदल चलने वालों के लिये सबसे बड़ी समस्या अब सड़क को पार करने की रहेगी। पहले चार लेन को तो जैसे-तैसे पार कर भी लेते थे अब छ: लेन पार करना और भी कठिन हो जायेगा। पैदल व साइकिल चालकों की सरकार द्वारा अनदेखी के चलते इस मार्ग पर दुर्घटनाओं में मरने व जख्मी होने वालों की संख्या का बढना निश्चित है।

क्या मन्त्री कृष्णपाल कभी इस ओर ध्यान देने की जहमत उठायेंगे? या उनका ध्यान कमाई में हिस्सा झटकने पर है?